प्रेषक

डा० राकश क्नार राधिव.

उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

निदेशक विद्यालयी शिक्षा एत्तराखण्ड दहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांकः 16 मार्च, 2009

विषय:

वित्तीय वर्ष 2008-09 में राजकीय इण्टर कालेज, रानीचौरी जनपद-टिहरी के

चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि को खोकृति।

महोदया.

उपर्धुक्त विषयक आपके मत्रांक-5 ख1/49248/जीर्ण-शीर्ण/2008-09, दिनांक: 13 फरवरी, 2009 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या: 127/माध्यमिक/2001, दिनांक: 21.12. 2001 एवं शासनादेश संख्या: 524/XXIV-3/08/02(125)2005; दिनांक: 26 मार्च, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज, रानीचौरी, टिहरी के चालू भवन निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू० 247.18 लाख के सापेक्ष अब तक स्वीकृत धनराशि २०० २४०.७५ लाख को समायोजित करते हुए देव अवशेष धनराशि रू० ६.४३ लाख (रूपये छ: लाख तिरालिस हजार मात्र) को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/08/02(37)2008; दिनांक: 16 अप्रैल, 2008 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू० 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्थ रवीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रवान करते है:-

- (1)-- आगणन में उत्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा रवीकृत/अनुमोदित दरों पर तथा शिड्यूल आफ रेट में रवीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदम करना आवश्यक हागा तदापरान्त ही आगणन की रवीकृति मान्य हागी।
- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानवित्र गठित कर नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्मस है, स्वीकृत नार्मस से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्यों की समयबद्धता के साथ वर्ष के अन्त तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया ज्यमा।
- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी रा स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।



- (5)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के नददे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य का सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- (6)— कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली—भाति निरीक्षण उच्च—अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- (7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो सांशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदायि न किया जाय।
- (8)- निर्माण सामग्रे। की प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- (9)— निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजैन्सी उत्तरदायी होगी।
- 2-- उपर्युवत धनराधि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यका हो, यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक रवीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराधि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित धनराशि से अधिक व्यय कदारि न किया जाय।
- 3.— इस शबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के अधीन लेखाशीपंक-4202-शिक्षा, खेल-कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-मध्यमिक शिक्षा-00-आयोजनागत-11-राजकीय हाईस्कूल व इण्टरनीढिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण-शीर्ण भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4:- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 267/XXVII(1)/2008; दिनाँकः 27 मार्च, 2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय.

(डा० राकेश कुमार) सचिव।

पुष्ठांकन	संख्याः 248(1)/XXI		V-3/09/02(125)2005;		तद्दिनांक।		
4	प्रतिलिपिः	निम्नलिखित	को	सूचनार्थ	एवं	आवश्यक	कार्यवाही	हेतु	प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, दंहरादून।
- 2- निजी सचिव, मां० मुख्य मंत्री जी ।
- 3- निजी सचिव मा० शिक्षा मंत्री जी.।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5-	अधिका	गडवाल	मण्डल-	पाडी

co. L.	पा-	
His	शः	****



6- अपर शिक्षा निदशक गढवाल मण्डल चोडी।

7- जिलाधिकारी, दिहरी।

8- जांगधिकारी हिहरी।

9- जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी।

10- दित्त अनुमाग-3 / नियोजन प्रकान्त,

11- वजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदंशालय, संविवालय परिसर।

12- कम्पूटर सल (वित्त विभाग)

13- एन०आइ०सी०, सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड दहरादून।

14- सन्बन्धित निर्माण एउन्सी।

18- रक्षित पत्रावर्ता

आज्ञा से,

(पी०एल०शाह) उप सचिव।

3/19